



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 14 सितम्बर, 2004/23 माघपद, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

प्रधिसूचना

शिमला-2, 14 सितम्बर, 2004

संख्या एल० एल० आर०-डी० (6) 76/2004-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 13-9-2004 को प्रख्यातित

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (2004 का अध्यादेश संख्यांक 2) को संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

2004 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्या 2

**हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (संशोधन)
अध्यादेश, 2004**

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 (2004 का 9) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2004 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह 15 मई, 2004 को प्रवृत्त होगा और सदैव प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2004 का 9

2. हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 50 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:— धारा 50-क का जोड़ना।

“50-क. हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड का उत्पादन और उसकी परिसम्पत्तियों तथा देनदारियों का अन्तरण.—(1) इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्राधिकरण की स्थापना की तारीख से ही हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम, 1972 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड उत्पादित हो जाएगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के उत्पादन की तारीख से ही—

(क) हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के अध्यक्ष सहित सदस्यों का पद धारण करना समाप्त हो जाएगा ;

(ख) सभी सम्पत्तियाँ, निधियाँ और शोध्य रकमों, जो हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड में निहित हैं या उसके द्वारा वसूली योग्य हैं, प्राधिकरण में निहित हो जाएंगी और उसके द्वारा वसूली योग्य होंगी ; और

(ग) ऐसी सभी देनदारियाँ जो हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के विरुद्ध प्रवर्तनीय हैं, प्राधिकरण के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगी।

(3) इस धारा की कोई भी बात, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम, 1972 के अधीन प्रत्याभूत उधार या ङिवेंचरों की बाबत राज्य सरकार की देनदारियों को प्रभावित नहीं करेगी।

- (4) उप-धारा (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के उत्पादन से ठीक पहले की गई सभी संविदाएं, करार और अन्य लिखत और जिनमें बोर्ड पक्षकार है या जो बोर्ड के पक्ष में है, प्राधिकरण द्वारा, के साथ या के लिए की गई समझी जाएगी।
- (5) सभी वाद, अपीलें या अन्य विधिक कार्यवाहियां जो हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड द्वारा या उसके विरुद्ध उप-धारा (1) के अधीन इसके उत्पादन से ठीक पहले, संस्थित हैं या जो संस्थित की जा सकती थीं, प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जाएंगी या संस्थित की जाएंगी।

स्पष्टीकरण.--इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए विधिक कार्यवाहियों के अन्तर्गत भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 1) के अधीन कोई कार्यवाही सम्मिलित है।

- (6) हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के सभी कर्मचारी, उप-धारा (1) के अधीन इसके उत्पादन की तारीख से ही प्राधिकरण के कर्मचारी हो जाएंगे और प्राधिकरण में सेवा के उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर पद धारित करेंगे और इस रूप में तब तक बने रहेंगे जब तक कि उनकी सेवा निबन्धन और शर्तों, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, प्राधिकरण द्वारा परिवर्तित नहीं कर दी जाती है।
- (7) उप-धारा (6) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के किसी भी कर्मचारी ने, उप-धारा (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के उत्पादन की तारीख से ठीक बाद के तीन मास के अवसान से पूर्व किसी भी समय प्राधिकरण को, प्राधिकरण का कर्मचारी न बनने के अपने आशय की, लिखित में नोटिस द्वारा, सूचना दी हो तो वह प्राधिकरण का कर्मचारी नहीं रहेगा और ऐसे उपदान, भविष्य निधि और सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं प्राप्त करने का हकदार होगा जैसी उसे हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के नियमों या अनुमोदन (आथोराइजेशन) के अधीन इसके उत्पादन के ठीक पहले साधारणतया अनुज्ञेय है।
- (8) यदि कोई ऐसा विवाद या ऐसी शंका उद्भूत होती है कि इस धारा के अधीन हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड की कौन सी सम्पत्तियां, अधिकार या देनदारियां प्राधिकरण को अन्तर्गत की गई हैं या बोर्ड के अधीन सेवारत कर्मचारियों में से, किन्हीं प्राधिकरण के कर्मचारी के रूप में माना जाना है, तो ऐसे विवाद या शंका को राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

बिष्णु सदाशिव कोफ़्जे,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।

सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

जिमना :
तारीख

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H. P. Ordinance No. 2 of 2004.

THE HIMACHAL PRADESH HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY (AMENDMENT) ORDINANCE, 2004

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Fifty-fifth year of the Republic of India.

An Ordinance to amend the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority Act, 2004 (Act No. 9 of 2004).

WHEREAS the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it, necessary for him to take immediate action.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. (1) This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority (Amendment) Ordinance, 2004.

Short title and commencement.

9 of 2004 (2) It shall and shall always be deemed to have come into force on the 15th day of May, 2004.

2. After section 50 of the Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority Act, 2004, the following new section shall be added, namely:—

Addition of section 50-A.

“50-A. *Abolition of the Himachal Pradesh Housing Board and transfer of its assets and liabilities.*—(1) On and with effect from the date of establishment of the Authority under section 3 of this Act, the Himachal Pradesh Housing Board established under the Himachal Pradesh Housing Board Act, 1972 shall stand abolished.

10 of 1972

(2) On and with effect from the date of abolition of the Himachal Pradesh Housing Board under sub-section (1)—

(a) the members including the Chairman of the Himachal Pradesh Housing Board shall cease to hold office ;

- (b) all properties, funds and dues which are vested in or realizable by the Himachal Pradesh Housing Board shall vest in and be realizable by the Authority; and
- (c) all liabilities which are enforceable against the Himachal Pradesh Housing Board shall be enforceable against the Authority.
- (3) Nothing in this section shall effect the liabilities of the State Government in respect of loans or debentures guaranteed under Himachal Pradesh Housing Board Act, 1972.
- (4) All contracts, agreements, and other instruments entered into immediately before the abolition of the Himachal Pradesh Housing Board under sub-section (1) and to which the Board is a party or which are in favour of the Board shall be deemed to have been entered into by, with or for the Authority.
- (5) All suits, appeals or other legal proceedings instituted or which could have been instituted by or against the Himachal Pradesh Housing Board, immediately before its abolition under sub-section (1), shall be continued or instituted by or against the Authority.

Explanations.—For the purpose of this sub-section, legal proceedings includes any proceedings under the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act 1 of 1894).

- (6) All employees of the Himachal Pradesh Housing Board shall, on and from the date of its abolition under sub-section (1), become employees of the Authority, and shall hold office in the Authority on the same terms and conditions of service and shall continue as such unless and until their terms and conditions of service are altered by the Authority with the previous approval of the State Government.
- (7) Notwithstanding anything contained in sub-section (6), where any employees of the Himachal Pradesh Housing Board, by notice in writing given to the Authority at any time before the expiry of three months next following the date of abolition of the Himachal Pradesh Housing Board under sub-section (1), has intimated his intention of not becoming an employee of the Authority, he shall cease to be an employee of the Authority and shall be entitled to get such gratuity, provident fund and other retirement benefits as are ordinarily admissible to him under the rules or authorization of the Himachal Pradesh Housing Board immediately before its abolition.

-
- (8) If any dispute or doubt arises as to which of the properties, rights or liabilities of the Himachal Pradesh Housing Board transferred to the Authority or as to which of the employees serving under the Board are to be treated as employees of the Authority under this section, such dispute or doubt shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final.

